



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 27 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी और मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया।



22 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदनों ने तेज़ी से पारित कर दिया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वास्तविक धन वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाना और नियामक निगरानी में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है।

- एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025, अनियमित ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े नुकसानों को रोकने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है। यह विधेयक 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और अगले ही दिन राज्यसभा में उल्लेखनीय रूप से पारित हो गया - जो एक तेज़-तर्रार विधायी प्रयास को दर्शाता है।

- इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाना है—ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जहाँ उपयोगकर्ता संभावित मौद्रिक लाभ के लिए पैसा, क्रेडिट या टोकन दांव पर लगाते हैं, चाहे परिणाम कौशल पर आधारित हों या संयोग पर।

ऐसे खेलों का विज्ञापन, वित्तीय सुविधा या प्रचार भी गैरकानूनी है।

- महत्वपूर्ण बात यह है कि नया कानून खिलाड़ियों को दंडित नहीं करता; बल्कि, ऐसे गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन करने वाले सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और वित्तीय सुविधा प्रदाताओं पर जवाबदेही का कड़ा प्रावधान करता है। उल्लंघन पर तीन साल तक की कैद और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, विज्ञापन संबंधी अपराधों के लिए दो साल तक की कैद और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और बार-बार अपराध करने पर पाँच साल तक की कैद और ₹2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है।

Key Points:-

(i) सुदृढ़ प्रवर्तन और भावी शासन सुनिश्चित करने के लिए, यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण गठित करने (या किसी मौजूदा निकाय को ये शक्तियाँ प्रदान करने) का अधिकार देता है। इस प्राधिकरण के पास खेलों का वर्गीकरण करने, अनुमत "ई-स्पोर्ट्स" या "ऑनलाइन सोशल गेम्स" के पंजीकरण का प्रबंधन करने और नियामक निगरानी स्थापित करने की शक्तियाँ होंगी।

(ii) राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही विधेयक को अधिनियम का रूप मिल गया है, और अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संबंधित नियमों और प्रवर्तन तंत्रों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। MeitY सचिव, एस. कृष्णन ने पुष्टि की है कि यह कानून आधिकारिक अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा, और जहाँ तक संभव हो, इसके कुछ हिस्से नियम बनाने से पहले ही लागू हो सकते हैं।

(iii) अंततः, यह कानून एक दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाता है: नागरिकों—विशेषकर युवाओं और परिवारों—को वित्तीय संकट और शोषण से बचाना और साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के लिए

एक विनियमित वातावरण को बढ़ावा देना। इससे रोज़गार, नवाचार और डिजिटल रचनात्मक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद है।

2. भारत ने पशु रक्त बैंकों और आधान के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए।



अगस्त 2025 में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) के तहत भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने देश के पहले व्यापक दिशानिर्देशों का अनावरण किया - पशु चिकित्सा रक्त आधान सेवाओं के लिए मानक प्रक्रियाओं और बुनियादी ढाँचे की स्थापना।

● भारत के पशुधन क्षेत्र में 537 मिलियन से अधिक पशु शामिल हैं, जबकि साथी पशुओं की संख्या 125 मिलियन से अधिक है - जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 5.5 प्रतिशत और कृषि GDP में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं - जिससे शुरू की गई पशु चिकित्सा आधान दिशानिर्देश खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान बन गए हैं।

● भारत में पशुओं के लिए रक्त आधान और रक्त बैंकों हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किए गए "दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs)" पशु चिकित्सा देखभाल में लंबे समय से

चली आ रही कमी को पूरा करते हैं। इससे पहले, रक्त आधान आपात स्थितियों में मानक दाता जाँच, रक्त समूहन या भंडारण प्रोटोकॉल के बिना ही किया जाता था।

● इस ढाँचे के तहत, रक्त आधान प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए अब रक्त समूहन और क्रॉस-मैचिंग अनिवार्य है। दिशानिर्देश दाता की पात्रता को भी स्पष्ट करते हैं—जिसमें स्वास्थ्य, टीकाकरण की स्थिति, आयु, वजन और रोग जाँच जैसे मानदंड शामिल हैं—और सूचित सहमति और दाता अधिकार चार्टर द्वारा समर्थित स्वैच्छिक, गैर-पारिश्रमिक दान पर जोर दिया गया है।

Key Points:-

(i) बुनियादी ढाँचे और समन्वय में सुधार के लिए, दिशानिर्देशों में जैव सुरक्षा-अनुपालन सुविधाओं वाले राज्य-विनियमित पशु चिकित्सा रक्त बैंकों के निर्माण का प्रस्ताव है। वे एक राष्ट्रीय पशु चिकित्सा रक्त बैंक नेटवर्क (N-VBBN) की भी परिकल्पना करते हैं जिसमें डिजिटल रजिस्ट्री, रीयल-टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग और एक आपातकालीन हेल्पलाइन शामिल होगी।

(ii) शिक्षा और क्षमता निर्माण इस ढाँचे के केंद्र में हैं: ट्रांसफ़्यूजन मेडिसिन मॉड्यूल को स्नातक (BVSc और AH), स्नातकोत्तर, और सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (CVE) पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों के प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि देश भर में सुरक्षित प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाया जाए।

(iii) दिशानिर्देश भविष्य के नवाचारों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं - दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल संग्रह इकाइयों को प्रोत्साहित करना, दुर्लभ रक्त प्रकारों के लिए क्रायोप्रीजर्वेशन तकनीक, और वास्तविक समय में दाताओं और प्राप्तकर्ताओं का मिलान करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन - आपातकालीन तैयारी और दीर्घकालिक पशु चिकित्सा देखभाल बुनियादी ढाँचे दोनों को मजबूत करना।

3. नेपाल वैश्विक बिग कैट संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल हो गया।



अगस्त 2025 में, नेपाल भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) का एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक रूप से सदस्य बन गया। यह एक बड़ा कदम है जो बिग कैट संरक्षण में सीमा पार सहयोग को बढ़ाता है, जिसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सात बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

● नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल होने से इसकी सदस्यता संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिसमें अब भारत, आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथियोपिया, इस्वातिनी, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया, सूरीनाम और नेपाल शामिल हैं। यह विस्तार विभिन्न महाद्वीपों में लुप्तप्राय बिग कैट्स की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता की बढ़ती वैश्विक मान्यता को रेखांकित करता है।

● IBCA की शुरुआत मूल रूप से 9 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के मैसूर में "प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में" कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस गठबंधन की परिकल्पना बाघ-क्षेत्र और गैर-क्षेत्र वाले देशों को

सात प्रमुख प्रजातियों - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा - के संरक्षण हेतु एक मंच के रूप में की गई थी।

● आंकड़ों के अनुसार, नेपाल ने अपनी बाघ आबादी को 2009 में मात्र 121 से बढ़ाकर 2022 में 355 कर दिया है, जो दक्षिण एशिया के संरक्षण प्रयासों की सबसे उल्लेखनीय सफलताओं में से एक है। यह उपलब्धि नेपाल को बाघ संरक्षण में वैश्विक अग्रणी देशों में शामिल करती है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत की प्रगति को और पुष्ट करती है।

Key Points:-

(i) फरवरी 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईबीसीए की औपचारिक स्थापना को मंजूरी दे दी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में होगा। मंत्रिमंडल ने IBCA के संचालन को मजबूत करने और वन्यजीव संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्षों (2023-24 से 2028-29) के लिए ₹150 करोड़ के बजटीय समर्थन को भी मंजूरी दी।

(ii) IBCA के लिए नोडल एजेंसी को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) नामित किया गया है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन कार्यरत है। NTCA को समन्वय, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और नीति संरक्षण का कार्य सौंपा गया है ताकि देश विभिन्न भू-दृश्यों में बाघों की आबादी के प्रबंधन और संरक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान कर सकें।

(iii) IBCA के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 23 जनवरी, 2025 को हासिल हुई, जब नई दिल्ली में संधि-आधारित समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस आयोजन ने भारत के साथ-साथ आर्मेनिया, भूटान, इथियोपिया, इस्वातिनी, ग्वाटेमाला, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम जैसे देशों को एक साथ लाया, जिससे गठबंधन की कानूनी नींव और वैश्विक

वन्यजीव संरक्षण के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता मज़बूत हुई।

4. अमित शाह ने प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल की 100वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया।



24 अगस्त, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री (MHA) अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय (MoC) के साथ मिलकर दिल्ली विधान सभा, नई दिल्ली में दो दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो विठ्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधान सभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष (अध्यक्ष) बनने की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।

- सरदार वल्लभभाई पटेल के बड़े भाई विठ्ठलभाई पटेल का जन्म 27 सितंबर, 1873 को गुजरात के करमसद में हुआ था और वे एक स्वतंत्रता सेनानी और सुधारवादी के रूप में उभरे।

- उन्होंने शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के साथ काम किया, और औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों के लिए राजनीतिक सुधार, स्वशासन और विधायी प्रतिनिधित्व की वकालत की।

- 1925 में, विठ्ठलभाई पटेल ने ब्रिटिश सिविल सेवक फ्रेडरिक व्हाइट को हराकर केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष (अध्यक्ष) चुने जाने वाले पहले भारतीय

बनकर इतिहास रच दिया। उनके नेतृत्व ने संसदीय स्व-प्रतिनिधित्व के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।

Key Points:-

(i) केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा परिसर में "वीर विठ्ठलभाई पटेल गौरव कथा" विषय पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में पटेल की यात्रा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा विधायी सुधारों में उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया।

(ii) इस स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में, विठ्ठलभाई पटेल के चित्र और केंद्रीय विधान सभा भवन को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। यह डाक टिकट भारतीय डाक और संचार मंत्रालय (MoC) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।

(iii) इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के दौरान दो फ्लिप पुस्तकें भी लॉन्च की गईं—एक विठ्ठलभाई पटेल के जीवन और योगदान पर और दूसरी दिल्ली विधानसभा के दशकों के परिवर्तनकारी इतिहास पर। इन पहलों का उद्देश्य पटेल की विरासत को उजागर करना और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

INTERNATIONAL

1. ओमान ने पर्यटन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दस लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा।



ओमान ने हाल ही में विजन 2040 के अंतर्गत अपने व्यापक पर्यटन विस्तार और आर्थिक विविधीकरण रणनीति के तहत प्रतिवर्ष दस लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के साहसिक लक्ष्य की घोषणा की है, जो 2024 में लगभग 700,000 है।

- ओमान का लक्ष्य भारतीय पर्यटकों की संख्या को प्रतिवर्ष दस लाख तक बढ़ाना है, जो 2024 में आए लगभग 700,000 भारतीय पर्यटकों के अतिरिक्त है। यह पहल ओमान के भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का लाभ उठाने के इरादे को रेखांकित करती है।

- सल्तनत का पर्यटन जोर उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों को आकर्षित करने पर है, जिसमें लक्जरी यात्रा, गंतव्य विवाह, बैठक-प्रोत्साहन-सम्मेलन-प्रदर्शनी (MICE), और साहसिक पर्यटन जैसे रेगिस्तान सफारी, पर्वत ट्रेक और सांस्कृतिक अनुभव शामिल हैं।

Key Points:-

(i) ओमान का विरासत और पर्यटन मंत्रालय जयपुर और अन्य भारतीय शहरों में आयोजित "फोकस ओमान" रोड शो के माध्यम से अपने प्रस्तावों को व्यापक रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसमें बहु-चैनल अभियानों का उपयोग किया जा रहा है, जो ओमान के परिदृश्य, विरासत और आगंतुक-अनुकूल वीजा नीतियों पर प्रकाश डालते हैं।

(ii) इस प्रयास का एक प्रमुख कारण ओमान (मस्कट)

और प्रमुख भारतीय शहरों के बीच बढ़ी हुई उड़ान कनेक्टिविटी है, साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए सरलीकृत ई-वीजा या आगमन पर वीजा नीतियां हैं, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और निर्बाध हो गई है।

(iii) यह पर्यटन अभियान ओमान के दीर्घकालिक विकास ब्लूप्रिंट—विज़न 2040—के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और सतत पर्यटन को प्राथमिकता देना है। ओमान 2040 तक सालाना लगभग 11.7 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की मेज़बानी करना चाहता है, और इस उपलब्धि को हासिल करने में भारत की केंद्रीय भूमिका है।

2. अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और जाम्बिया सरकार ने 2025 तक फार्मास्यूटिकल विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया।



अगस्त 2025 में, भारत के अग्रणी अनुबंध विकास एवं विनिर्माण संगठन (CDMO), अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने ज़ाम्बिया में एक संयुक्त उद्यम (JV) दवा निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए ज़ाम्बिया सरकार (GRZ) के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सुविधा ज़ाम्बिया के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और क्षेत्रीय निर्यात के लिए दवाओं की आपूर्ति को बढ़ावा देगी।

● नई दवा परियोजना अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और ज़ाम्बिया सरकार (GRZ) के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। Akums के पास 51% की बहुलांश हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष 49% ज़ाम्बिया की सरकारी संस्थाओं के पास होगी।

● समझौते के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी को दिसंबर 2025 तक निगमित किया जाना है, तथा नई ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल सुविधा का संचालन 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह समय-सीमा घरेलू दवा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़ाम्बिया के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है।

● प्रस्तावित सुविधा में मौखिक ठोस, तरल इंजेक्शन और बीटा-लैक्टम उत्पादों सहित दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये दवाएं मुख्य रूप से ज़ाम्बिया की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करेंगी और आयातित दवाओं पर निर्भरता कम करने, किफायती और सुलभ उपचार सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगी।

Key Points:-

(i) खरीद व्यवस्था के तहत, ज़ाम्बिया सरकार (GRZ) ने 2026-2027 की अवधि में न्यूनतम 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 425 करोड़ रुपये) मूल्य की दवाइयाँ खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। ज़ाम्बिया संयंत्र के चालू होने तक, इन दवाओं का निर्माण और आपूर्ति भारत में अकम्स की सुविधाओं में की जाएगी।

(ii) स्थापना के बाद, यह सुविधा दक्षिणी अफ्रीका के लिए एक फार्मास्यूटिकल केंद्र के रूप में कार्य करेगी। यहाँ उत्पादित दवाइयाँ ज़िम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, मलावी, तंजानिया और मोज़ाम्बिक जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात की जाएँगी, जिससे अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की फार्मास्यूटिकल उपस्थिति मज़बूत होगी।

(iii) यह साझेदारी एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा साझेदार

के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है। अकम्स-जीआरजेड संयुक्त उद्यम न केवल ज़ाम्बिया में रोज़गार सृजित करेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को भी मज़बूत करेगा और दवाओं की कमी को कम करेगा। यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

BANKING & FINANCE

1. SEBI ने IDBI बैंक में LIC को सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दी।



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI बैंक) में प्रमोटर शेयरधारक से सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत होने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है, जो बैंक के निजीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।

● अगस्त 2025 में, SEBI ने पुनर्वर्गीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो IDBI बैंक के निजीकरण के लिए एक पूर्व शर्त है। जून 2025 तक, LIC के पास IDBI बैंक में 49% हिस्सेदारी थी, जिससे यह भारत सरकार के साथ सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक बन गया।

● पुनर्वर्गीकरण के लिए LIC को SEBI की सख्त शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें 10% तक सीमित मताधिकार, IDBI बैंक पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं, बोर्ड में प्रतिनिधित्व का अभाव, तथा दो वर्षों के भीतर अपनी हिस्सेदारी को अनिवार्य रूप से घटाकर 15% या उससे कम करना शामिल है।

Key Points:-

(i) SEBI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि LIC द्वारा इन शर्तों का पालन न करने पर पुनर्वर्गीकरण स्थिति स्वतः रद्द हो जाएगी, जिससे IDBI बैंक के चल रहे निजीकरण रोडमैप पर असर पड़ेगा।

(ii) विनिवेश योजना के तहत, भारत सरकार और LIC की संयुक्त रूप से IDBI बैंक में 94.72% हिस्सेदारी है, जिसमें भारत सरकार की 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। दोनों हितधारकों ने रणनीतिक बिक्री के माध्यम से संयुक्त रूप से अपनी 60.7% हिस्सेदारी बेचने पर सहमति व्यक्त की है।

(iii) IDBI बैंक के निजीकरण के लिए वित्तीय बोली प्रक्रिया अक्टूबर और दिसंबर 2025 के बीच होने वाली है, जिससे SEBI की यह मंजूरी भारत के व्यापक बैंकिंग क्षेत्र सुधारों और विनिवेश एजेंडे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन जाएगी।

2. मलेशिया ने दुनिया का पहला AI-संचालित बैंक, Ryt Bank लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, मलेशिया ने Ryt Bank लॉन्च किया, जो स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित बैंक है। यह पहल मलेशिया के तेज़ी से डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक फिनटेक नवाचार में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

● Ryt Bank को मलेशिया की YTL ने सिंगापुर की टेक फर्म Sea Limited के सहयोग से विकसित किया है, जो डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में एक मील का पत्थर साझेदारी है। यह परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए सीमा पार सहयोग पर ज़ोर देती है।

Key Points:-

(i) यह बैंक Ryt AI एप्लिकेशन द्वारा समर्थित है, जो बहुभाषी है और वर्तमान में बहासा, मलेशिया और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, और सितंबर 2025 तक मंदारिन भाषा में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह इसे विविध उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया पहला बहुभाषी AI-संचालित डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाता है।

(ii) Ryt AI एक हमेशा चालू बैंकिंग सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो मलेशिया के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) ILMU द्वारा संचालित है, जो बुद्धिमान, स्वचालित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बैंकिंग सेवाएँ

सुनिश्चित करता है। नए राइट बैंक को आधिकारिक तौर पर देश के केंद्रीय बैंक, बैंक नेगारा मलेशिया द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

3. जापान की SMBC को यस बैंक में 25% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है।



भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC), जो सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. (SMFG) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक, यस बैंक लिमिटेड में 24.99% तक की चुकता पूंजी और मतदान अधिकार प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े सीमा-पार निवेशों में से एक है।

- मई 2025 में, SMBC ने लगभग ₹13,483 करोड़ मूल्य की द्वितीयक हिस्सेदारी खरीद के माध्यम से यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक निश्चित समझौता किया।

- यह निवेश भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए SMBC की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह भारत के बैंकिंग उद्योग में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में से एक है।

- RBI द्वारा स्वीकृत सौदे में कुल 24.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है, जिसमें 13.19% हिस्सेदारी सीधे SBI से खरीदी गई है, जो यस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसके अतिरिक्त, शेष 6.81% हिस्सेदारी सात अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों से सामूहिक रूप से अधिग्रहित की जाएगी, जिनमें ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (KMBL), एक्सिस बैंक लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड और बंधन बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

Key Points:-

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्टीकरण के अनुसार, SMBC को दी गई मंजूरी एक वर्ष तक वैध रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि SMBC को यस बैंक के प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, हालाँकि उसके पास बैंक की लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी है, जिससे भारतीय बैंकिंग नियामक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।
- (ii) यह अधिग्रहण बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BRA), 1949, बैंक शेयरों के अधिग्रहण पर RBI के दिशानिर्देश और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 सहित नियामक ढांचे के अधीन है।
- (iii) यह लेनदेन न केवल भारत में पूंजी प्रवाह को मजबूत करता है बल्कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और भविष्य की विकास क्षमता में बढ़ते वैश्विक निवेशक विश्वास को भी उजागर करता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की 'BBB-' दीर्घकालिक रेटिंग की पुष्टि की।



25 अगस्त, 2025 को, तीन सबसे बड़ी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक, फिच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (IDR) को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'BBB-' पर पुनः स्थापित किया। यह रेटिंग मजबूत विकास के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है, लेकिन उच्च सरकारी ऋण और अमेरिकी टैरिफ के खतरों से उत्पन्न जोखिमों को भी उजागर करती है।

● न्यूयॉर्क और लंदन स्थित फिच रेटिंग्स ने हाल ही में भारत की रेटिंग 'BBB-' पर बरकरार रखी है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग स्केल के तहत सबसे निचली निवेश-ग्रेड रेटिंग है।

● 'BBB' रेटिंग मध्यम ऋण जोखिम और पर्याप्त पुनर्भुगतान क्षमता को दर्शाती है, जबकि माइनस (-) चिह्न उस ग्रेड में सबसे निचले स्तर को दर्शाता है। 'BBB-' से नीचे की कोई भी डाउनग्रेडिंग भारत को सट्टा या "जंक" स्थिति में धकेल देगी, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी और विदेशी निवेश सीमित हो जाएगा।

● इस पुनर्पुष्टि को वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बल मिलता है, जो 'BBB' औसत 2.5 प्रतिशत से काफी अधिक है। यह वृद्धि घरेलू मांग, स्थिर निजी खपत और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (CapEx) कार्यक्रमों

द्वारा संचालित हो रही है। फिच ने रेखांकित किया कि भारत की विविध अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन और बाह्य वित्तीय स्थिरता इसकी प्रमुख ताकतें हैं।

Key Points:-

(i) तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) के टैरिफ उपायों से जोखिम उजागर हुए हैं, जहां कुछ भारतीय निर्यातों पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की घोषणा की गई थी, विशेष रूप से रूस से तेल आयात के संबंध में।

(ii) फिच ने GDP पर सीमित प्रत्यक्ष प्रभाव की आशंका जताई है, लेकिन व्यापार प्रवाह और कारोबारी धारणा पर नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoCI) व्यापार विविधीकरण के माध्यम से इन चुनौतियों को कम करने पर काम कर रहा है।

(iii) राजकोषीय मोर्चे पर, फिच ने वित्त वर्ष 26 में सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 81.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही उच्च ब्याज-से-राजस्व अनुपात भी। हालाँकि, सरकार ने इस वर्ष राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। GST को दो स्लैब (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) में युक्तिसंगत बनाने सहित सुधार प्रस्तावों को राजकोषीय स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में कदम के रूप में देखा गया। एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के बुनियादी ढाँचे मजबूत होने के बावजूद, भविष्य में किसी भी रेटिंग उन्नयन के लिए निरंतर राजकोषीय सुधार आवश्यक होंगे।

2. पूर्व CRPF DG अनीश दयाल सिंह को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया।



भारत सरकार (GoI) ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के पूर्व महानिदेशक (DG) अनीश दयाल सिंह को 24 अगस्त, 2025 से प्रभावी नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में नियुक्त किया है। वह सीधे NSA अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे।

- मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अनीश दयाल सिंह दिसंबर 2024 में सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

- अब उन्हें भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने में सहायता हेतु एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भूमिका सौंपी गई है। इस पद के लिए उनके चयन में उनकी व्यापक पुलिसिंग और खुफिया पृष्ठभूमि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी नई भूमिका में, सिंह मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें जम्मू-कश्मीर (J&K) में सुरक्षा की देखरेख, वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद संबंधी चुनौतियों का प्रबंधन शामिल है। अर्धसैनिक बलों के नेतृत्व में उनका व्यापक अनुभव इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने में सहायक होगा।

Key Points:-

(i) इस नियुक्ति से पहले, अनीश दयाल सिंह ने

लगभग तीन दशक तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में सेवा की, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को संभाला। बाद में, उन्होंने महानिदेशक के रूप में आईटीबीपी और CRPF का नेतृत्व किया और सीमा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में अग्रिम पंक्ति के परिचालन अनुभव प्राप्त किया।

(ii) CRPF महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सिंह ने 2024 के लोकसभा (संसद का निचला सदन) आम चुनावों और पुनर्गठन के बाद जम्मू-कश्मीर में होने वाले पहले विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण तैनाती की भी निगरानी की। जटिल सुरक्षा अभियानों की देखरेख करने की उनकी क्षमता ने उन्हें उच्च-स्तरीय कार्यों के लिए एक विश्वसनीय अधिकारी बना दिया है।

(iii) अपनी नियुक्ति के साथ, सिंह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अधीन काम करेंगे और भारत की आंतरिक सुरक्षा नीतियों को आकार देने में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में योगदान देंगे। उनके नेतृत्व से उग्रवाद, आतंकवाद और उभरते आंतरिक खतरों के विरुद्ध भारत की तैयारियों को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. डॉ. राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया।



23 अगस्त, 2025 को, BRICS देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय ऋणदाता, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर डॉ. राजीव रंजन को पाँच साल के कार्यकाल के लिए अपना उपाध्यक्ष (VP) और मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) नियुक्त किया। यह रणनीतिक पदोन्नति व्यापक आर्थिक नीति और वित्तीय प्रशासन में उनकी व्यापक विशेषज्ञता को दर्शाती है।

• डॉ. राजीव रंजन की NDB में उपाध्यक्ष और मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) के पद पर पदोन्नति भारत और बैंक दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। यह ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक वित्तीय तनाव, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं और प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के बीच, बढ़ रहा है, जिससे बैंक के जोखिम ढाँचों की सुरक्षा में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

• डॉ. रंजन 1989 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुए और एक केंद्रीय बैंकर के रूप में एक गहन करियर बनाया। मई 2022 से, वे कार्यकारी निदेशक और मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और भारत में मौद्रिक और तरलता नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने RBI के मौद्रिक नीति विभाग का नेतृत्व किया और एमपीसी के सचिव के रूप में कार्य किया।

Key Points:-

(i) RBI में अपने कार्यकाल के अलावा, डॉ. रंजन ने RBI के अंतर्राष्ट्रीय विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग में भी कार्यभार संभाला। 2012 से 2015 तक, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान में आर्थिक नीति विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। उन्होंने RBI के आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग का भी नेतृत्व किया और डेटा-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा दिया।

(ii) डॉ. रंजन के व्यापक वैश्विक अनुभव में भारत का प्रतिनिधित्व करना और G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD), और SAARC जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में नीतिगत चर्चाओं में भाग लेना शामिल है। कई आर्थिक प्रकाशनों और तीन सह-लेखकीय पुस्तकों के लेखक होने के नाते, उनकी विद्वत्तापूर्ण साख और भी निखरती है।

(iii) मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में, डॉ. रंजन NDB के जोखिम प्रबंधन, रणनीतिक योजना, नीति निर्माण, साझेदारियों और पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ESG) कार्यों की देखरेख करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन और विकासात्मक वित्तपोषण पर केंद्रित वैश्विक मंचों में बैंक की भागीदारी का भी नेतृत्व करेंगे - जिससे वैश्विक दक्षिण की बहुपक्षीय वित्तीय प्रणाली में भारत का प्रभाव और मज़बूत होगा।

SPORTS

1. अनुभवी भारतीय टेस्ट स्टार चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है।



24 अगस्त 2025 को, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज चेतेश्वर अरविंद पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 37 साल की उम्र में, इस मज़बूत दाएँ हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ ने एक दशक से भी ज़्यादा लंबे अपने शानदार करियर का अंत किया और अपने धैर्य, धैर्य और उत्कृष्ट तकनीक से एक अमिट विरासत छोड़ी।

- पुजारा ने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना अंतिम मैच खेला। 103 टेस्ट मैचों में, उन्होंने 43.60 की प्रभावशाली औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने पाँच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी भाग लिया, हालाँकि उनका असली प्रभाव लाल गेंद के प्रारूप में रहा।

- अंतरराष्ट्रीय खेल के अलावा, पुजारा का घरेलू रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 66 शतकों सहित 21,301 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिससे घरेलू क्रिकेट, खासकर सौराष्ट्र के लिए, उनकी पहचान एक मज़बूत स्तंभ के रूप में स्थापित हुई है। उनकी अटूट एकाग्रता और निरंतरता ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों में से एक बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय खेल के अलावा, पुजारा का घरेलू रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 66

शतकों सहित 21,301 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिससे घरेलू क्रिकेट, खासकर सौराष्ट्र के लिए, उनकी पहचान एक मज़बूत स्तंभ के रूप में स्थापित हुई है। उनकी अटूट एकाग्रता और निरंतरता ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों में से एक बना दिया है।

Key Points:-

(i) चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद क्रिकेट जगत से श्रद्धांजलियाँ उमड़ पड़ीं। महान ओपनर सुनील गावस्कर ने उनकी सराहना करते हुए कहा, "चेतेश्वर, आपको नमन। आपने भारत को गर्व महसूस कराया है," वहीं विराट कोहली ने उन्हें धन्यवाद दिया कि नंबर 3 पर उनकी निरंतर मौजूदगी ने उनका नंबर 4 का काम आसान बना दिया। प्रशंसकों, खिलाड़ियों और कमेंटैटर्स ने उन्हें एक "आधुनिक दौर का टेस्ट मैच योद्धा" और शास्त्रीय बल्लेबाजी अनुशासन का प्रतीक बताया, जिन्हें उनकी दृढ़ता, धैर्य और टेस्ट क्रिकेट के प्रति अटूट समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

(ii) पुजारा ने खुलासा किया कि 24 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा करने से पहले वह केवल एक सप्ताह के लिए सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे थे। जबकि यह अध्याय बंद हो गया है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट में "किसी भी तरह" से योगदान करने की इच्छा व्यक्त की है – संभवतः मेंटरशिप, कमेंट्री या विकासात्मक भूमिकाओं के माध्यम से।

2. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया और MCA शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया।



23 अगस्त, 2025 को, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने वानखेड़े स्टेडियम में एमसीए शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया और संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की, साथ ही अनुभवी प्रशासक शरद पवार की भी प्रतिमा स्थापित की - जो मुंबई में खेल के इतिहास और प्रशासन दोनों के प्रति श्रद्धांजलि है।

- 8,000 वर्ग फुट में फैले नए MCA शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का भव्य उद्घाटन हुआ। इसके प्रवेश द्वार पर, आगंतुकों का स्वागत सुनील गावस्कर और शरद पवार की आदमकद प्रतिमाओं द्वारा किया जाता है, जो शहर की क्रिकेट उत्कृष्टता और प्रशासनिक नेतृत्व का प्रतीक हैं।

- सुनील गावस्कर ने गहरा आभार व्यक्त करते हुए इस सम्मान को "अद्वितीय" बताया और बताया कि एमसीए ने उनके शुरुआती दिनों से ही उनका कितना साथ दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास "शब्द नहीं हैं" और भावनात्मक रूप से इस सम्मान को मुंबई क्रिकेट में अपने सफ़र से जोड़ा।

- संग्रहालय के अंदर, आगंतुकों को भौतिक यादगार वस्तुओं, इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों और उन्नत डिजिटल डिस्प्ले का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। चयनित खंड मुंबई के क्रिकेट सितारों, महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों, विश्व कप की सफलताओं, प्रशासकों और सदस्य क्लबों को

श्रद्धांजलि देते हैं, जो पुरानी यादों और तकनीकी तल्लीनता दोनों का अनुभव प्रदान करते हैं।

Key Points:-

(i) MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने इस संग्रहालय को शरद पवार और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने मुंबई क्रिकेट और प्रशासनिक प्रशासन को आगे बढ़ाने में शरद पवार के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने संग्रहालय की वैश्विक क्षमता पर प्रकाश डाला और इसकी तुलना लॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित क्रिकेट संग्रहालयों से की।

(ii) यह संग्रहालय 22 सितंबर, 2025 से जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से खुलेगा। इसका निर्माण न केवल मुंबई के खेल बुनियादी ढांचे को समृद्ध करेगा, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा, क्रिकेट की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगा और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व जल सप्ताह 2025, 24 से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक जल चुनौतियों पर केंद्रित होगा।

WORLD WATER WEEK 2025

Observed from August 24 to 28, Focuses on Climate Action and Global Water Challenges



विश्व जल सप्ताह (WWW), वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने वाला अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रतिवर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका

35वाँ संस्करण 24 से 28 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जलवायु कार्रवाई, स्थिरता, स्वच्छता और स्वच्छ जल तक समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- विश्व जल सप्ताह का 2025 संस्करण "जलवायु कार्रवाई के लिए जल" विषय पर केंद्रित है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुकूल होने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और जैव विविधता के हास जैसे परस्पर जुड़े संकटों पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि जल समाधान कैसे एक स्थायी और जलवायु-अनुकूल भविष्य के निर्माण में मदद कर सकते हैं।

- स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान (SIWI) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला विश्व जल सप्ताह, जल मुद्दों पर सबसे प्रमुख वैश्विक आयोजन बन गया है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को स्वच्छ जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित करता है।

- विश्व जल सप्ताह का आयोजन मीठे पानी के संसाधनों से लेकर महासागरों तक, संपूर्ण जल चक्र के एकीकरण पर जोर देता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और सतत प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके। समानता और जलवायु न्याय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर के कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदाय जल और स्वच्छता के एजेंडे में पीछे न छूट जाएँ।

Key Points:-

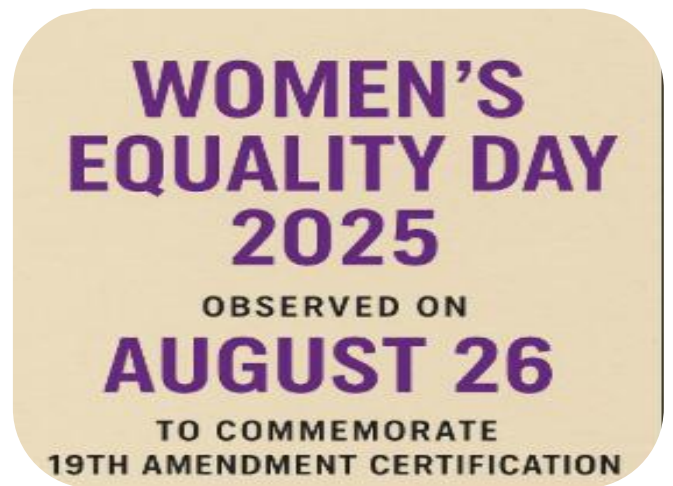
(i) इस आयोजन का इतिहास 1991 से शुरू होता है, जब स्टॉकहोम ने स्वच्छ जल का जश्न मनाने वाले एक सार्वजनिक उत्सव के साथ-साथ पहली स्टॉकहोम जल

संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस उद्घाटन संगोष्ठी ने दुनिया भर के प्रमुख जल वैज्ञानिकों को आकर्षित किया और जल-संबंधी मुद्दों पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी।

(ii) 2001 में, स्टॉकहोम जल संगोष्ठी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर स्टॉकहोम में विश्व जल सप्ताह कर दिया गया, जिससे मीठे पानी और स्थिरता पर चर्चा के लिए एक प्रीमियम वैश्विक मंच के रूप में इसकी पहचान मजबूत हुई।

(iii) तब से, यह आयोजन वैश्विक स्तर पर जल संकट से निपटने के लिए नवीन नीतियों, अनुसंधान-आधारित प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बन गया है।

2. महिला समानता दिवस 2025 19वें संशोधन प्रमाणन के उपलक्ष्य में 26 अगस्त को मनाया गया।



महिला समानता दिवस, जो प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है, 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन के प्रमाणन का प्रतीक है, जिसने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। 1970 के दशक की शुरुआत में स्थापित, यह दिवस महिलाओं के मताधिकार की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और पूर्ण लैंगिक समानता की दिशा में चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।

- 19वां संशोधन, जिसे "सुसान बी. एंथनी संशोधन" के नाम से भी जाना जाता है, लिंग के आधार पर

मताधिकार से वंचित करने पर रोक लगाता है। हालाँकि इसका अनुसमर्थन पहले ही हो चुका था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त, 1920 को प्रमाणित किया गया, जिससे महिलाओं के मताधिकार को एक संवैधानिक वास्तविकता बना दिया गया।

• 1971 में, कांग्रेस सदस्य बेला अब्जुग (डेमोक्रेट-न्यूयॉर्क) ने 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद 1970 में 19वें संशोधन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समानता के लिए महिलाओं की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। 1972 में, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पहली बार "महिला अधिकार दिवस" की घोषणा की, जिसके बाद 1973 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। तब से, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने प्रतिवर्ष इस दिवस की घोषणा की है।

Key Points:-

(i) महिला समानता दिवस की जड़ें 1848 के सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में निहित हैं, जिसने अमेरिका में औपचारिक महिला अधिकार आंदोलन को प्रज्वलित किया। एलिजाबेथ कैडी स्टैटन जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, मताधिकार आंदोलन दशकों की वकालत के माध्यम से विकसित हुआ, जिसकी परिणति 19वें संशोधन के साथ विधायी सफलता के रूप में हुई।

(ii) महिला समानता दिवस ऐतिहासिक जीतों का सम्मान तो करता है, लेकिन साथ ही अधूरे कामों पर भी चिंतन करने का आह्वान करता है। लैंगिक वेतन अंतर, नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व और अंतर्विभागीय असमानताएँ जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। यह दिवस लैंगिक न्याय, नागरिक भागीदारी और मतदान के अधिकार से परे समानता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थागत सुधारों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO ने ओडिशा तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।



अगस्त 2025 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इन परीक्षणों ने विविध हवाई खतरों के विरुद्ध भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को प्रमाणित किया।

• एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) में उन्नत मिसाइल और भविष्य की हथियार तकनीकों का संयोजन शामिल है। इसमें मध्यम दूरी की अवरोधन क्षमता के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (QRSAM), निकट-सीमा की मारक क्षमता के लिए उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) और भविष्य की अवरोधन क्षमताओं के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) शामिल हैं।

• QRSAM (क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल) को DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के सहयोग से विकसित किया है। यह मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली हवाई खतरों का त्वरित प्रतिक्रिया अवरोधन प्रदान करती है, जिससे

एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क में स्तरीकृत सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- VSHORADS (अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली) को DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) द्वारा विकसित किया गया है। इसे निकट-सीमा रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कम ऊँचाई वाले हवाई खतरों को निशाना बनाता है, जिससे महत्वपूर्ण सैन्य और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कवच मिलता है।

Key Points:-

(i) DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र (CHESS) द्वारा विकसित निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW), भारत की रक्षा क्षमताओं में एक भविष्य की छलांग का प्रतीक है। यह उच्च-शक्ति लेज़र-आधारित प्रणाली ड्रोन और अन्य मानवरहित प्लेटफार्मों जैसे आधुनिक हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध उन्नत अवरोधन प्रदान करती है।

(ii) रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा विकसित केंद्रीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (CCC) ने सभी हथियार प्रणालियों के समन्वित संचालन का प्रबंधन किया। एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर, ओडिशा में मान्य किए गए पहले परीक्षण में मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) और मल्टी-कॉप्टर ड्रोन सहित तीन अलग-अलग प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया और सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया।

(iii) यह सफल परीक्षण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वायु रक्षा क्षमता को मज़बूत करता है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 (15 अगस्त 2025) पर घोषित "सुदर्शन चक्र" मिशन को बल प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य उभरते हवाई खतरों के विरुद्ध भारत का मज़बूत बहुस्तरीय रक्षा कवच स्थापित करना है।

Static GK

Nepal	राजधानी : काठमांडू	प्रधान मंत्री (PM) : खड्गा प्रसाद (के.पी.) शर्मा ओली
Ministry of Home Affairs (MHA)	केंद्रीय मंत्री : अमित शाह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Oman	राजधानी: मस्कट	मुद्रा: ओमानी रियाल
SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
Malaysia	प्रधान मंत्री: अनवर इब्राहिम	आधिकारिक भाषा: मलय
Zambia	राजधानी : लुसाका	राष्ट्रपति : हाकेंडे हिचिलेमा
Japan	प्रधान मंत्री: शिगेरु इशिबा	राजधानी: टोक्यो
DRDO	अध्यक्ष: डॉ. समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
New Development Bank (NDB)	अध्यक्ष: डिल्मा रूसेफ	मुख्यालय: शंघाई, चीन